श्रीमती सरला माहेश्वरी : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि 1984 में भारत की ओर से एक विशेष दल इजरायल भेजा गया था और उस दल ने इजरायल के विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की थी ? अखबारों में यह बात आई है कि इस बैठक के जरिए भारत ने बहुत से गुप्त समाचार इजरायल के दल को दे दिये लेकिन बदले में भारत को कुछ नहीं मिला । इसके इलावा मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि ए०टी०टी०ई० को वहां ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके जरिये से भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इजरायल और भारत के बीच में यह जो नई विकासमान धुरी पैदा की जा रही है क्या इससे भारत की अब तक चली आ रही नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO : This question is separate and needs a separate answer.

MR. CHAIRMAN : It deals with the External Affars Ministry rather than the Defence Ministry. You know it all. *(Interruptions) I*t is not a question which the Defence Minister will answer. This is a question for the External Affairs Miistry. Shrimati Sarala Maheshwari.

श्री चतुरानन मिश्र : एक मिनिस्ट्र दूसरे के विभाग के बारे में स्टेटमेंट दे देता है (व्यवधान) डिफेंस मिनिस्टर आंतरिक मामलों पर स्टेटमेंट दे देता है, इसी से तो गड़बड़ी पैदा होती है (व्यवधान)

SHRI R. K. KARANJIA : Mr. Chairman, the question that I was about to ask has been well answered by the Prime Minister. So I will not insist on it. My point was that pf we *shy* off collaboration with Mossad, who do they expect us to seek cooperation with ? Terrorists

MR. CHAIRMAN : Next question.

Equity shares of M/s. Suzuki Motor Corporation in Maruti Udyod Limited

*42. DR. RATNAKAR† PANDEY :
SHRI S. MADHAVAN :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have permitted M/s. Suzuki Motor Corpo-tation to raise its equity share in the Maruti Udyog Limited from 40 per cent to 50 per cent and if so, what are the details thereof and the reasons therefor ;

(b) whether this would help the company to get loans from the International Finance Corporation ; and if so, what are the details thereof; and

(c) whether it is a fact that Govern ment would loose administrative control over the company and if so, what steps are proposed to be taken to safeguard its interests in this company ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to
(c) Govt, has allowed Suzuki Motor Corporation to raise its equity capital in the Maruti Udyog Ltd. (MUL) from 40% to 50% to facilitate financing of MUL's ex-pansion project meant largely for export, through additional foieign equity and foreign loans. After the share of Suzuki Motor Corporation goes up to 50% MUL would cease to be a Govt, company and would become eligible for loans from the Intemtional Finance Corporation.

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Ratnakar Pandey.

Govt. would be able to safeguard its interests by virtue of its right as a shareholder and through its nominees on the Board of Directors of the Company.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, संजय गांधी की परिकल्पना मारुति मोटरकार की थी और यह हमारे उद्योग मंत्रालय का राष्ट्रीय उद्योग बना और जो सुजूकी मोटर कंपनी जापान की है, उसके सहयोग से इस योजना को आगे बढ़ाया गया और 40 से 50 प्रतिशत अंशदान उनका हो जाने से सरकारी नियंत्रण उस पर से हट गया और यह प्राइवेट अंश या हिस्सा बन गई। सरकार अल्पदाता के रूप में अपने अधिकारों तथा कंपनी के निदेशक मंडल में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी हितों की रक्षा करने में सफल हो सकेगी।

जवाब में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हो जायेगी यह कंपनी और आज ही अखबार में, जन सत्ता में मैंने पढ़ा है कि 46 निरुत्तर सांसद और उनके विशेषाधिकार मारुति उद्योग में भ्रष्टाचार के 12 मामलों की जांच आखिर सी०बी० आई० को क्यों नहीं करने दी जा रही है और 46 सांसदो ने इस संदर्भ में प्रश्न किया है और मारुति के काम करने का जो तरीका है, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि जब जे० बेंगलराव जी उद्योग मंत्री थे, तो हम लोगों ने आग्रह किया था। इस पर बाराणसी में एक मारुति की एजेंसी के लिए उन्होंने आदेश दिया। उसका विज्ञापन हुआ और जब नई सरकार आई, तो उस एजेंसी को वी०पी० सिंह जी ने समाप्त कर दिया और उसकी जानकारी, आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से मैं बताना चाहता हूं, कि आपके दोनों उद्योग मंत्रियों को मैंने दी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

तो क्यों इस तरह की चीजें होती हैं? सरकारें बदलती हैं, लेकिन नीतियां नहीं बदलती हैं। क्यों इस तरह का नीति में परिवर्तन हुआ, इसकी जानकारी मैं चाहता हूं और मारुति उद्योग के संबंध में क्या मारुति उद्योग जापान के मै० सुजुकी मोटर के साथ इस संबंध में कोई मैमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडींग पर हस्ताक्षर किया है?

यदि किया है, तो उसका पूरा विवरण क्या है?

मै० सुजुकी मोटर कार्पोरेशन की ईक्विटी शेयर बढ़ने से पूरे मारुति उद्योग पर तथा वहां कार्यरत इंजीनियर, मजदूर तथा अन्य कर्मचारियों पर किस प्रकार का असर पड़ने की संभावना है, इसकी जानकारी मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं।

SHRI P. K. THUNGON : Sir, as I have stated already in my main answer, the main purpose of giving them up to 50 per cent is to enable the Maruti Udyog to get loans from the International Finance Corporation. And secondly, we have to have an expansion of up to 70,000 cars in the Maruti Udyog and for that we do not have funds to invest from ourselves, and more so in foreign exchange. That is why this decision was required to be taken.

Sir, as regards the management of the Company, we have really sentimental attachment to Maruti as Congressmen because it was established by Shri Sanjay Gandhi. So, we had referred it to the Foreign Investment Promotion Board, and they have deliberated in detail and they have recommended that the present CMG post may be split into Chairman and Managing Director, and one of them can be nominated by us and the other can be nominated by the Suzuki Motors. And likewise, equal number of Directors can be nominated.

Thirdly, so far as expansion of Maruti agencies is concerned, the Maruti Udyog produces a little over one lakh vehicles. There are 56 Maruri dealers all over the country and distribution of these one lakh vehicles through these 56 agencies is supposed to be economical. If more and more agencies are given, it is not going to

be economical for the dealers, and that is the reason why for the last two years, no dealership agency has been given from Maruti Udyog Limited.

So far as workers' interest is concerned, we have already been in touch with the union of the workers and we have assured them that so far as our part is concerned, we will see that their interest is protected to the extent possible.

डा० रत्नाकर पांडेय : महोदय, मेरे पहले प्रश्न का शुरू का अंश अनुत्तरित रह गया है मंत्री महोदय से । सरकार की नीतियां बदलती हैं, नीतियां नहीं बदलती हैं सरकारें बदलती हैं । एक उद्योग मंत्री ने एक विज्ञापन किया कि बनारस में, वाराणसी में जहां से 11 सांसद और 48 विधायक आते हैं वहां मारुति की एजेंसी दी जाए । उसके बाद उसको बंद कर दिया गया । क्या यह सत्य नहीं है कि उसके चेयरमैन श्री भार्गव के एक रिश्तेदार को इलाहाबाद में उसकी एजेंसी दी गयी जो वाराणसी में भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है । इसमें चेयरमैन इंटरेस्टेड हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सरकार से, दोनों मंत्रियों से बात की गई लेकिन वह नहीं किया गया । उसका क्या कारण है जबकि एक उद्योग मंत्री ने इस चीज को कहा और आपने, दूसरे उद्योग मंत्री ने रोका । जब नयी सरकार आई तो उस चीज को सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए तैयार नहीं है । उसका गोलमाल जवाब दे रहे हैं ।

दूसरा, जो सी०बी०आई० का मामला चल रहा है उसमें बड़े आक्षेपात्मक ढंग से सरकार पर आक्रमण अखबार कर रहे हैं । मैं प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिन सांसदों ने इस संबंध में शिकायत की है उनकी मीटिंग बुला करके उनकी जो शिकायतें हैं उनकी जानकारी लें क्योंकि वे नेगोशिएशन और बातचीत से मामलों को हल करने में पूरा विश्वास करते हैं । इसलिए इस काम को करें । इसी संदर्भ में मेरे पहले प्रश्न का जो अनुत्तरित अंश है उसका स्वयं उद्योग मंत्री जो जवाब दें तो ज्यादा स्पष्ट होगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बारबार मारुति कारों की कीमतों में वृद्धि से तथा इन कारों में विदेशी पुर्जों की बहुतायत होने से मारुति गाड़ियों की बिक्री में भारी गिरावट आई है जिससे सरकार को सुजुकी को 50 परसेंट शेयर देने के लिए मजबूर होना पड़ा है । इस समय मारुति उद्योग द्वारा कितनी गाड़ियां वर्कशाप में तैयार खड़ी हैं जिन्हें कोई लेने वाला नहीं है क्या सरकार ने मारुति को बाजार में पब्लिक डिबेंचर्स फ्लोट करने की अनुमति दी है । इसका ब्यौरा क्या है ..(व्यवधान) क्वेश्चन ही हैं । ए०बी०सी०डी० है । इस समय सरकार की मारुति उद्योग में कितनी पूंजी लगी हुई है और निजीकरण के बाद क्या परिस्थिति होगी । निजीकरण के पश्चात् मारुति उद्योग अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा इसकी क्या संभावनायें हैं ।

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMHA RAO) : It is not a Question ; this is a detailed questionnaire. He will send answers to each of these questions in this questionnaire. I do not thin we should really devote time on this now. In my case, we cannot be expected to have all the information readily available now. It has to be accurate information which I would like to give to the Member.

SHRI S. MADHAVAN : Sir, will the government inform us whai. will be the Government's equity after the foreign company raises its equity ? Wiii the Government lose its administrative control over the firm whicn it had before raising the foreign company's equity ?

THE Maruti Udyog Limited is a public limited company. It is not a Government department. Do the international financial corporations insist on increasing the foreign equity in this company ? If so, why ? Is the Government aware of the experience of a highly developed country like the United States, with the Japanese

industry, especially, the automobile industry ? The United States is now experiencdng difficulties because of the domination of the Japanese industry in their country. Will the Govenment consider this aspect beofre raising the equity ?

SHRI P. K. THUNGON : At present, the equity share is as under. Government—59.76 per cent. Suzuki Motors—40 per cent. Maruti Udyog Employees' Mutual Benefit Fund— .24 per cent. If the share of Suzuki Motors is increased from 40 per cent to 50 per cent, in terms of face value, another Rs. 22 crores will be the increase. But the valuation of the shares is being done by the CCI. These are being worked out. We are still negotiating with the Suzuki Motors. So far as control is concerned. I have mentioned the broad guidelines which were alreday re-commended.

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, अभी मंत्री जी ने बताया कि मारुति उद्योग लिमिटेड के विस्तार के लिए इस कंपनी में सुजुकी की जो इक्विटी पूंजी है वह बढ़ाकर 50 करोड़ करने के प्रस्ताव की स्वीकृति सरकार ने दे दी है। इस विस्तार कार्यक्रम के तहत जैसे मंत्री जी ने बताया कि लगभग प्रतिवर्ष 70 हजार अतिरिक्त गाड़ियों का उत्पादन होगा मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इसमें से कितनी गाड़ियां निर्यात के लिए रखी जायेंगी और कितनी गाड़ियां हमारे देश में ही उपयोग के लिए रखी जायेंगी ? साथ ही निर्देशक मंडल के गठन की जो घोषणा माननीय मंत्री जी ने की है उसका मापदंड क्या होगा, उसका गठन कब तक हो जायेगा ? और इस इक्विटी शेयर के बढ़ने से मारुति उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? उन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसके लिए सरकार की क्या कार्य योजना है ?

SHRl P. K. THUNGON : So far as the pattern is concerned as to how many directors will be there, who will have the Chairmanship, who will have the Managing Directorship, etc., it will be decided very soon. We are negotiating with them. We have given out proposals. We are awaiting their proposals. We are still negotiating.

The export expectation, after the expansion of 70,000 vehicles per year is effected, is, 40—50,000 in the European markets and another 10— 15,000 in the other markets.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : माननीय सभापति जी, यह मारुति उद्योग में सुजुकी मोटर्स कार्पोरेशन के इक्विटी शेयर्ज 40 से 50 प्रतिशत बढ़ने का तय हुआ है, इससे जो प्राईवेट कंपनीज जिनका प्रभाव बढ़ता है शेयर्ज के अनुसार ही उनके प्रभाव की बढ़ोत्तरी होती है तो जब प्राइवेट कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं तो उसका निश्चित रूप से उस पर एड-मिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ज्यादा होता है। अभी पचौरी जी ने यह प्रश्न किया था कि उस उद्योग के कर्मचारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए क्या किया जा रहा है? उसी संदर्भ में मैं आगे एक और जानकारी चाहता हूं कि प्राइवेट कंपनियां ज्यादातर मैक्सीमम बैनेफिट के आधार पर काम करती हैं और उसी आधार पर अपने कर्मचारियों को एम्प्लाय करती हैं। यह निश्चित है कि जब किसी प्राइवेट कंपनी को ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होगा तो वह अपने कर्मचारियों को कम करेगी और उनका रिट्रेंचमेंट होगा। ऐसी दशा में सबसे ज्यादा प्रभावित वे लोग होंगे जोकि बाद में भर्ती हुए होंगे जैसाकि आम तौर पर सीनियरिटी बेसिस पर होता है और उसमें भी ज्यादातर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा कई बार देखा गया है। तो मैं माननीय मंत्रीजी और विशेष रूप से माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि यदि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों का रिट्रेंचमेंट वगैरा होता है तो क्या आप उनको निर्देशित करेंगे कि उनका रिट्रेंचमेंट न हो ? आपकी उनसे ऐसी कोई बातचीत हुई है या ऐसा फैसला लिया गया है या आगे ऐसा फैसला लेंगे और इस बारे में कोई आश्वासन देंगे ?

SHRI P. K. THUNGON : It is a fact that when it becomes a private company, the Board of Directors will be the decision-making body. The Board is the decision-making body. What we can do is, through our members of the Board we will be able to control this and I assure that so far as Maruti Udyog is concerned, no retrenchment is going to take place.

श्री अजीत जोगी : सभापति : महोदय जब तक मारुति उद्योग एक सार्वजनिक उपक्रम रहा तब तक उसमें कार्यरत जितने जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे, वह लोक सेवा की परिभाषा में आते थे और अगर भ्रष्टाचार के प्रकरण थे तो उन पर भ्रष्टाचार नियमों के अंतर्गत कार्यवाही हो सकती थी, लेकिन अब चूंकि वह सार्वजनिक उपक्रम नहीं रहा, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि जैसाकि पिछले कई वर्षों से लगातार सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन उद्योग मंत्रालय से अनुमति चाह रहा है कि मारुति उद्योग के चेयरमैन और कुछ अन्य अधिकारियों पर अन्वेषण किया जाय और उन पर मुकदमा भ्रष्टाचार के तहत चलाया जाय तो अब चूंकि मारुति उद्योग एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं रह गया है और उसके चैयरमैन और दूसरे अधिकारी अब "लोक सेवक" की परिभाषा में नहीं आते हैं, तो क्या उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिन पर सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन लगातार कार्यवाही करने की अनुमति उद्योग मंत्रालय से मांग रहा है, अब उन प्रकरणों को समाप्त मान लिया जाएगा और वे भ्रष्टाचार के सारे प्रकारण खत्म कर दिए जायेंगे ?

SHRI P. K. THUNGON : Sir, though it is not directly related to this question, I would like to state that there are certain allegations to which J have replied in one of the Parliament Questions that they are under censideraticn of the Government.

SHRI MURASOLI MARAN : Sir, this is the first case of privatisation, that is, giving a public sector undertaking to a private sector and that too to a foreign company. Mr. Madhavan put a relevant question. He asfcea how you were going to have administrative control after having given the equity of 50 per cent to Suzuki and the Minister replied that they are still negotiating with the company wnether to take over the Chairmanship or the Managing Directorship. It is very strange. Why did you not negotiate before permitting 50 per cent equity to the company ? It is now like putting the cart before the horse. This is the first case. Why are you capitulating to a foreign company ? You should have decided first and then only you should have acted. You have permitted to give 50 per cent equity in advance and now you are negotiating. That means, you are in a weaker position. Wfca prevented you to start negotiation first ? This is my first question. Part (b) of my question is, are there any export obligations attached to it ? Do you insist that by dollar value or by any other foreign exchange value this company should give export obligation because recently the Reserve Bank of India hasamen ded the FERA? So, no more export obligation is necessary for new companies, except for the old companies which have signed earlier. So, what is the position of Suzuki ? Will trey come under new companies, which means they have no export obligation ? Secondly, what is the dividend position ? Is the company allowed to take away all the dividend or are you putting a ceiling ? I want a direct reply from the honouble Minister.

SHRI P. K. THUNGON : Sir, so far as Maruti Udyog Limited is concernea, as it is, today, it is still a Government company.. .*(Interrep-tions)*.. .We have not yet entered into an agreement with them ; we have not signed any greement as yet. That is why I have stated that we are negotiating and we are trying to take the maximum possible advantage.

SHRI MURASOLI MARAN : When you are in a position to dictate, why do you negotiate ? .. *.(Interruptions)*.. .Before off-loading, why do you negotiate ? You should have put it as a condition.

SHRI DIPEN GHOSH : Why did not the Government ensure that ?

MR. CHAIRMAN : They have not off-loaded as yet.

SHRI P. KL. THUNGON : Sir, so far as the next part of the question is concemed-whether there is any export obligation—I would like to state that we have, this year, exported about 16,061 Maruti cars.

SHRI MURASOLI MARAN : That is why my question. Sir, whether there is any export obligation.

MR. CHAIRMAN : Let him answer.

SHRI P. K. THUNGON : Sir, the main purpose of the expansion is to export as I have already stated, 50,000—65,000 car per year to European and other masrkets.

SHRI MURASOLI MARAN :

Is it compulsory, is it an obligation ? That is my question. Is it an obli a-ti on, is it compulsory ?

SHRl P. K. THUNGON : Sir, It is with this understanding that Suzuki Motors have agreed, that they wiii stop their manufacture of small cars of their own and they will hand over that responsibility wholly and solely to Maruti Udyog Limited, because they have their European market and other markets. Not only that. They have offered to give their marketing facilities in Europe and some other countries and, therefore, the question of obiigation of export is certainly there.

About dividend, I would like to make it very clear to the honourable Member that they cannot take away their dividend until and unless they export a certain minimum amount..

SHRI MURASAI MARAN : What is the amount ?

SHRI P. K. THUNGON : But I would like to impress upon the honourable Member by facts and figures. Sir, this year, 1990-91, our export has been worth more than Rs. 71 or 73 crores. The dividend we have distributed...

SHRI YASHWANT SINHA : This is deliberate misleading of the House. When the matter is under negotiation...

MR. CHAIRMAN : Let him answer, please.

SHRl YASHWANT SINHA : He is misleadig the House, Sir. I am levelling a charge that the Minister is misleading the House.

MR. CHAIRMAN : You have no right to say that... *(Interruptions)* ...No, no. ...*(Interruptions)*... Wait a minute*(Interruptions)*.

SHRI T. R. BALU : Are they negotiating ? .. *.(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN : You must permit him—and by now he would have finished it. 1 didn't disturb you when many of you went away from the Question Hour. Now, today, when the Minister strats answering— he is telling you sometning—and before he is able to complete his answer if you start shouting, that is not good.

SHRI MURASOLI MARAN : We are not shouting, Sir.

MR. CHAIRMAN Let him complete.

SHRI MURASOLI MARAN : With whatever he has said, he has contradicted himself.

MR. CHAIRMAN : No. That is improper. He has already said

that only after whatever is exported on that basis the dividend will be permitted. That is what he has said.

SHRI T. R. BALU : Sir, unless they have arrived at a memorandum of understanding.. .*{Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : I have not called \ou. In the Question Hour, only the person whom I call, will speak. Others will not go on record.

आप सब लोग समझदार हैं ।

are all experienced people, senior people. Why do you do all this ? Kindly hear him.

SHRl P. K. THUNGON . The balancing of dividend would be over a period of seven years from the commencement of production. In addition to what I have said, I want to add this.

SHRI MURASOLI MARAN : Sir, he nas not answered my question. In view of the latest amendment of the FERA rules, this export obligation has been done away with. That is the latest position.

MR. CHAIRMAN : An agreement they are going into.

SHR MURASOLI MARAN : That is why I am asking you.

MR. CHAIRMAN : Shri S. S. Ahluwalia.

SHRI MURASOLI MARAN ; Sir, let him reply. Sir, I want to protest very much.

MR. CHIRAMAN : I have called Mr. S. S. Ahluwalia. *(Interruptions)*

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया कि यह जो शेयर "सुजूकी" के बढ़ा दिए गए तो इससे और भी प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी और उसमें कारों की एक्सपोर्ट की मात्रा और बढ़ाई जाएगी । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि कुछ दिन पहले मारिशियस में, जहां मारुति उद्योग लिमिटेड ने करीब 300 मारुति-1000 एक्सपोर्ट की थीं, वह इनके जहाज से ही क्वालिटी कंट्रोल से रिजेक्ट हो गईं और वापिस आ गईं ? इनका क्वालिटी कंट्रोल इतना पूअर है कि वहां जहाज पर खड़े-खड़े उन्होंने बन्दरगाह पर उतरने भी नहीं दिया और वे कारें वापिस भेज दी गईं।

श्री सभापति : वे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ है ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि यह जब प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, पिछले दिनों में, महीनों में देखा गया है कि सरकारों ने पेट्रोल की कीमत इसलिए बढ़ाई और उस पर एक्साइज इसलिए बढ़ाया ताकि पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो । तो मारुति उद्योग लिमिटेड कारों की जो प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो क्या उसका इनकी फ्यूल एफिशिएन्सी पर कोई कंट्रोल होगा ? इनके लिए कोई उन्होंने नियमावली बनाई है कि अगर इतनी फ्यूल एफिशिएन्सी में नहीं आएगी तो वह कार रिजेक्ट होगी ?

SHRI P. K. THUNGON : Sir. about the first part I have no information. I will try to collect information. So far 1 have no information about rejection. *{Interruptions)*

About the second part of the question one of the main purposes of establishing the Maruti Udyog Ltd. was to produce fuel-efficient vehicles and we will continue to do it. Even after Suzuki gets 50 per cent share, they will keep on improving it. Also for the information of the hon.

Member, fuel efficiency and safety measures which are required to be enhanced and improvised by 1993 are being taken care of.

Setting up of National Renewal Fund

*43. SHRI PRAGADA KOTAIAH :
SHRl JAGADISH JANI

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether Government have set up a National Renewal Fund ;

(b) if so, the details thereof and the objectives of the Fund and the amount earmarked for it for 1990-91;

(c) the names of the Ministries and other agencies which have contributed or may contribute to this Fund ;

(d) the manner in which the Fund is proposd to be administered ;

(e) the categories cf workers which are likely to be benefited by tne Fund ;

(f) whether any other similar fund is aiso proposed to be constituted to rehabilitate the displaced workers io the decentralised sectors because of competition from their mecnanised counter-parts ;

(g) whether the Central Government would provide similar funds to the States ; and

(h) if so, the details of fund to be provided to Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN) (a) to (h) A statement is laid on the Tabic of the House.

£The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagadish Jani.

Statement

(a) to (h) Government have constituted a National Renewal Fund. The fund will provide assistance to meeting costs of retraining and redeployment of labour and also provide compensation to labour in the event of restructuring of any industrial unit. The Fund would help technological upgradation and modernisation in Indian industry. The fund would cover both public and private enterprises with contributions from Government of India, State Governments, Financial Institutions, General Insurance Corporation of India and Industrial units.

The Fund will be administered by the Ministry of Industry. Procedures for administering the Fund are being worked out.

श्री जगदीश जानी : सभापति महोदय, राष्ट्रीय नवीकरण कोष का मैं स्वागत करता हूं । सरकार बहुत सारे उद्योगों को मेकेनाइज़ करने जा रही है, इनमें प्रचुर तादाद में श्रमिक काम करेंगे । क्या सबको इस राष्ट्रीय नवीकरण कोष से धनराशि की सहायता मिलेगी ?

SHRI P. J. KURIEN : In the process of restructuring our .echnolo-gical upgradation if the labour are affected, certainly the National Renewal Fund will come forward to arsist them.

श्री जगदीश जानी : मैंने राज्यों के बारे में जिक्र किया था, तो क्या राज्यों में ऐसे कोष की स्थापना होगी ? अगर होगी तो कब तक और इस विषय में क्या कदम उठाया गया है ? मंत्री महोदय ने धनराशि देने के बारे में जो बताया है, उड़ीसा राज्य को कितनी धनराशि दी जायेगी ?

SHRI P. J. KURIEN : It is up to the State Governments to decide whether they should like to have